Regarding payment of pending dues under MGNREGS-laid

श्री उम्मेदा राम बेनीवाल **(बाड़मेर) :** राजस्थान में मनरेगा के आज दिनांक तक मटेरियल सप्लायरों एवं मेट कारीगरों का राज्य में लगभग 3800 करोड़ और बाड़मेर जिले का 725 करोड़ रुपए भुगतान लंबित है । वर्ष 2022-23 के कुछ ग्राम पंचायतों में बिल जांच लंबित होने के कारण भुगतान अटका है, जबकि वर्ष 2023-24 के कार्यों के बिल पोर्टल पर फीड किए जा चुके हैं,उसमें मात्र 20% भुगतान ही हो पाया है । सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी प्रकार का भुगतान आरंभ ही नहीं हुआ है । जिससे ग्रामीण विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है । इन स्थितियों ने श्रमिकों, कारीगरों और मटेरियल आपूर्तिकर्ताओं को भारी वित्तीय संकट में डाल दिया है,जिससे पंचायतों में कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं ।कई लोगों ने निजी ऋण लेकर निर्माण सामग्री की आपूर्ति की, जो अब डिफॉल्ट की स्थिति में पहुँच गए हैं । यह देरी व स्थिति न केवल ग्रामीण विकास, आजीविका, सामाजिक संतुलन बल्कि अर्थव्यवस्था को प्रभावित व घातक सिद्ध कर रही है, योजना की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रही है । मेरा सरकार से आग्रह है कि विषय पर संज्ञान लेते हुए लंबित भुगतानों को शीघ्र करवाए और सिस्टम में व्याप्त तकनीकी, प्रशासनिक अवरोधों को दूर करने के साथ भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित की जाए ।